भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2299
जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2025 को दिया जाना है ।
17 श्रावण, 1947 (शक)

एआई को विनियमित करने के लिए कानून

2299. डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा टेक्सास रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस एक्ट और यूरोपीयन यूनियन एआई एक्ट की जांच हेतु प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ताकि विस्तृत अध्ययन के बाद सरकार भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विनियमित करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर सके;
(ख) बेहतर शासन प्रणाली के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या उपाय कार्यान्वित किए गए हैं; और
(ग) मंत्रालय द्वारा संबंधित हितधारकों के समन्वय में एआई के प्रयोग में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार प्रौद्योगिकी को सभी के लिए सुलभ बना रही है। इसका उद्देश्य वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास और उपयोग को लोकतांत्रिक बनाना है, जिससे अंततः विभिन्न क्षेत्रों में जीवन में सुधार आएगा।

सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) गवर्नेंस के लिए एक समावेशी और नवाचार-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने, डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था द्वारा समर्थित है।

दुनिया भर में कानूनी ढांचे का अध्ययन करने और हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद सरकारी एआई रणनीति बनाई गई है।

<u>भारत की एआई रणनीति:</u>

भारत की एआई रणनीति का उद्देश्य भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है। सरकार ने मार्च 2024 में इंडियाएआई मिशन शुरू किया। यह भारत के विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित एक सुदृढ़ और समावेशी एआई इकोसिस्टम स्थापित करने के लिये एक रणनीतिक पहल है।

एआई मिशन के सात स्तंभ इस प्रकार हैं:

1) **इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता:** इसका उद्देश्य एमएसएमई और स्टार्टअप सहित सभी को किफायती कीमत पर उच्च-स्तरीय कंप्यूट पावर (जीपीयू) प्रदान करना है।
2) **इंडियाएआई फाउंडेशन मॉडल:** भारतीय डेटासेट और भाषाओं पर प्रशिक्षित भारत के अपने बड़े मल्टीमॉडल मॉडल (एलएमएम) विकसित करना। इसका उद्देश्य जनरेटिव एआई में संप्रभु क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।
3) **एआईकोश:** एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए बड़े डेटासेट विकसित करना। एआईकोश एक एकीकृत डेटा प्लेटफ़ॉर्म है जो सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से डेटासेट को एकीकृत करता है।
4) **इंडियाएआई अनुप्रयोग विकास पहल:** इस स्तंभ का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शासन और सीखने की अक्षमताओं के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में भारत विशिष्ट चुनौतियों हेतु एआई अनुप्रयोगों को विकसित करना है।
5) **इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स:** एआई क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की संख्या में वृद्धि करके भारत में एआई कुशल पेशेवरों को विकसित करना। इसका उद्देश्य देश भर के टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब स्थापित करना भी है।

6) **इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग:** एआई स्टार्ट-अप को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

7) **सुरक्षित और विश्वसनीय एआई:** जिम्मेदार एआई अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ शासन ढांचे के साथ नवाचार को संतुलित करना।

<u>एआई को विनियमित करने के लिए तकनीकी-कानूनी दृष्टिकोण</u>

भारत की एआई रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ विनियमन के लिए इसका संतुलित और व्यावहारिक तकनीकी-कानूनी दृष्टिकोण है:

- भारत तकनीकी समाधानों के साथ कानूनी सुरक्षा प्रतिउपायों को जोड़ता है।
- सरकार आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों में आरएंडडी परियोजनाओं को वित्त पोषित कर रही है ताकि डीपफेक का पता लगाने, गोपनीयता बढ़ाने और साइबर सुरक्षा के लिए एआई उपकरण बनाए जा सकें।
- यह भारत के इस विश्वास को दर्शाता है कि प्रभावी एआई शासन को केवल कानून बनाने से आगे बढ़कर नवीन तकनीकी हस्तक्षेपों द्वारा समर्थित होना चाहिये।
- यह विशिष्ट मॉडल सुनिश्चित करता है कि नवाचार में बाधा न आए।

<u>सरकारी मंत्रालयों/विभागों के साथ कार्यशालाएं</u>

- मंत्रालय ने सरकारी विभागों में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने, शासन और सेवा दक्षता बढ़ाने के लिए कई प्रतिउपाय लागू किए है।
- एमईआईटीवाई ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्य विभागों के साथ कई कार्यशालाएँ आयोजित की हैं, जिनमें विभागीय चुनौतियों की पहचान करने और एआई-संचालित समाधानों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
    - ऐसी पहली कार्यशाला 5 अप्रैल 2024 को आयोजित की गई थी। तब से, 26 जून 2025 तक ऐसी कई कार्यशालाएँ आयोजित की जा चुकी है।
- इन कार्यशालाओं ने हितधारकों को इंडियाएआई मिशन के तहत विकसित किए जा रहे विभिन्न समाधानों से भी परिचित कराया, और संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा इन समाधानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
- इसके अतिरिक्त, मंत्रालयों और विभागों को एआईकोश में डेटा का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो एक पहल है जिसे सुदृढ़ एआई समाधान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि नवाचार डेटा-संचालित और सुविचारित हैं।

<u>आईजीओटी में एआई पाठ्यक्रम</u>

आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म सिविल सेवा अधिकारियों के लिए अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए एक कभी भी, कहीं भी, किसी भी डिवाइस पर सीखने का प्लेटफ़ॉर्म है। इसने एआई और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों को गहन रूप से अपनाया है, जो मंत्रालयों और राज्य सरकारों में डिजिटल कौशल और उन्नत तकनीकों पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है।

वर्तमान में, इस प्लेटफ़ॉर्म पर 60 से अधिक एआई और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनमें कुल मिलाकर 20.39 लाख से अधिक संचयी नामांकन और 14.66 लाख पाठ्यक्रम पूरे हो चुके हैं।

<u>एआई एकीकरण के लिए योग्यता फ्रेमवर्क</u>

भारत में एआई एकीकरण के लिये एक योग्यता फ्रेमवर्क शुरू किया गया है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को एआई प्रौद्योगिकियों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने, सार्वजनिक चिंताओं को जिम्मेदारी से दूर करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में नागरिक प्रतिक्रिया को शामिल करने हेतु आवश्यक कौशल से लैस किया जा सके।

<u>फ्यूचरस्किल्स प्राइम</u>

फ्यूचरस्किल्स प्राइम डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के रूप में उपलब्ध है, जिसे https://futureskillsprime.in/ पर होस्ट किया जाता है, जहां उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और आकांक्षाओं के अनुरूप कभी भी, कहीं भी सीखने की सुविधा के लिए प्रीमियम सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

अब तक, 22.79 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने एफएसपी पोर्टल पर साइन अप किया है और 13.44 लाख उम्मीदवारों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन/प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनमें से 3.41 लाख ने एआई/बिग डेटा में नामांकन/प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, सी-डैक और नाइलिट संसाधन केन्द्रों ने उभरती प्रौद्योगिकियों में 18,785 सरकारी अधिकारियों और 2,367 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। साथ ही, विभिन्न प्रौद्योगिकियों में 208 बूटकैंप आयोजित किए गए हैं जिसके तहत 19,929 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 2499 लाभार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित हैं।

*****